IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और उच्च शिक्षा: एक विश्लेषण

बृजेश कुमार यादव
शोध छात्र
शिक्षक शिक्षा संकाय
तिलकधारी स्नातकोतर माहाविद्यालय जौनपुर

सारांश:
किसी देश के आर्थिक और सामाजिक प्रगति उसके सुपरिभाषित, दूरदर्शी और भविष्यवादी शिक्षा नीति पर निर्भर करता है। प्रगतिशील देशों ने अपनी-अपनी परंपराओं और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को अपनाया है। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति,2020 (NEP,2020) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलना है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बदलाव लाएगा और इसे एक आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायसंगत में बदल देगा।
यह शोध लेख NEP, 2020 पर आधारित है जो उच्च शिक्षा (HE) पर केंद्रित है। लेख के लेखक पृष्ठभूमि और उद्भव पर चर्चा करना चाहते हैं; दृष्टि को उजागर करना, प्रमुख क्षेत्रों और सिद्धांत दिशानिर्देशों पर ध्यान केंद्रित करना; और आवश्यक रूप से हितधारकों के लिए सुविधाओं, प्रभाव क्षेत्रों और अवसरों को भी सामने लाने के लिए। अंत में, वे नीति के नियोजित, व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं।
प्रमुख शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा प्रणाली, प्रतिमान बदलाव, सतत विकास।

भूमिका:
पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक महत्व है। जबकि सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता के मामले में वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उत्थान और नेतृत्व की कुंजी है; वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति; राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का संरक्षण है। वर्तमान में, दुनिया ज्ञान और रोजगार के परिदृश्य में तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस परिदृश्य में, एक शिक्षा प्रणाली को चरित्र का निर्माण और आकार देना चाहिए; शिक्षार्थियों को नैतिक, तर्कसंगत, करुणामय और देखभाल करने में सक्षम बनाना कि वह एक लाभकारी रोजगार के लिए तैयार हो सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, के बीच की खाई को शिक्षा प्रणाली में सुधारों के माध्यम से पाट दिया जा सकता है। सुधार अनिवार्य रूप से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ECCE) से उच्च शिक्षा (HE) तक प्रणाली में गुणवत्ता, समानता और अखंडता लाते हैं। इसलिए, यह आवश्यक था कि भारत में सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए समान पहुंच वाली शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए।
इस संदर्भ में, भारत ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया है, जो समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना चाहता है; और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देता है। इस तरह के एक स्वप्निल लक्ष्य के लिए शिक्षा की प्रक्रिया को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुर्नव्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों यानी 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसलिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 (NEP,2020) पेश करके इसे सुधारने का फैसला किया। नई नीति में भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती हुई विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। यह नीति भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए, 21 वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं को संशोधित करने का प्रस्ताव करती है। NEP, 2020 प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता और उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देता है, जैसे कि महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान; और सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमता और स्वभाव भी। सबसे महत्वपूर्ण बात

यह है कि प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान और विचारों की समृद्ध विरासत ने इस नीति को बनाने में मार्गदर्शन किया है।

NEP,2020 का उदय:

बहुत पहले भारत की पहली शिक्षा नीति वर्ष 1986 में पेश की गई थी। इसके लगभग चौंतीस साल बाद, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 (NEP, 2020) नामक एक नई नीति पेश की गई। NEP, 2020 इस प्रकार 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की जगह लेता है। यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, जो निश्चित रूप से भारत को उच्च शिक्षा के लिए दुनिया भर में एक आकर्षक गंतव्य बना देगा।

भारत सरकार ने जनवरी, 2015 में इस शिक्षा नीति के लिए पहल की थी और इसके लिए वास्तविक परामर्श प्रक्रिया पूर्व कैबिनेट सचिव, श्री टी. एस. आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में शुरू की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जून, 2017 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष, डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा 2019 में नई शिक्षा नीति की मसौदा प्रस्तुत किया गया था। मसौदा नई शिक्षा नीति, 2019 को तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए। इसके बाद, मंत्रालय ने मसौदा नीति तैयार करने में एक कठोर परामर्श प्रक्रिया शुरू की तदुपरांत उभरने की प्रक्रिया में नए नीति दस्तावेज को अद्यतन, संशोधित और अंततः 29 जुलाई, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, जिसे 29 जुलाई, 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। नीति में भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नीति स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों दोनों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन और कल्पना करती है।

NEP, 2020:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 महत्वाकांक्षी और नाटकीय बदलाव लाएगी जो देश में शिक्षा प्रणाली को बदल सकता है। यह भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

i. दृष्टि(Vision): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य भारतीय लोकाचार में निहित एक वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, और नीचे दी गई चर्चा में दिए गए सिद्धांतों के साथ संरेखित करना है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदल जाए।

ii. महत्वपूर्ण क्षेत्र: NEP,2020 अनिवार्य रूप से पिछले कुछ दशकों से भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली गंभीर चुनौतियों का समाधान कर रहा है। नीति के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं:

- प्राथमिक शिक्षा में, खराब साक्षरता दर और संख्यात्मक परिणाम: कई रिपोर्टों से पता चलता है कि स्कूल में पांच साल बिताने के बावजूद 50% बच्चों में बुनियादी संख्यात्मकता यानी संख्याओं और साक्षरता को समझने और काम करने की क्षमता नहीं है। NEP,2020 मूल रूप से इस मूलभूत शिक्षा को एक मुख्य क्षेत्र के रूप में देखता है और इसका उद्देश्य छात्रों के बीच कई कौशल और क्षमताओं का विकास करना है।
- मध्य और माध्यमिक शिक्षा में, उच्च ड्रॉपआउट स्तर, पाठ्यक्रम असंगति: मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में कई राज्यों में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर में वृद्धि हुई है। स्कूल छोड़ने के पीछे कई कारण हैं, जैसे गरीबी, खराब स्वास्थ्य और स्कूल से दूरी। इसके अलावा, राज्यों, लिंग, जातीयता और वर्ग में स्कूल छोड़ने की दर में बड़े अंतर मौजूद हैं। यहां तक कि सकल नामांकन अनुपात (GER) भी काफी कम हो रहा है क्योंकि डेटा इंगित करता है कि नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात कक्षा 5 के बाद और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद छोड़ रहा है। इसलिए, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, विशेष रूप से मध्य और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भी नीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- उच्च शिक्षा में, बहु-विषयक दृष्टिकोण की कमी और विषय की पसंद, मूल्यांकन के साथ-साथ कौशल-अंतर के संबंध में लचीलेपन की कमी: उच्च शिक्षा संस्थानों में ड्रॉपआउट दर भी बढ़ रही है। साथ ही सकल नामांकन अनुपात (GER) घट रहा है और लगभग आधे से भी कम मध्य और माध्यमिक शिक्षा में है। इसका मतलब है कि कई छात्र उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं ले रहे हैं। इसलिए,

नीति मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में ड्रॉपआउट दर को कम करने और GEP बढ़ाने पर केंद्रित है।

- इसके अलावा, NEP,2020 के लिए समग्र जोर क्षेत्रों में बचपन की देखभाल, पाठ्यक्रम डिजाइन, भाषा / शिक्षा का माध्यम, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक मूल्यांकन, मूल्यांकन पैटर्न और मूल्यांकन और परीक्षा प्रारूप शामिल हैं। शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने के लिए एक नया मूल्यांकन केंद्र, पारख यानी समग्र विकास के ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण (PARAKH i.e. Performance, Assessment, Review and Analysis of Knowledge of Holistic Development) प्रस्तावित है।
- अंत में, विनियमन, शिक्षकों की भर्ती और विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य मानकों और मानदंडों की अनुपस्थिति के मुद्दे इस नई नीति में अतिरिक्त क्षेत्र है।

iii. सिद्धांत दिशानिर्देश: इस नीति के मूलभूत स्तंभ पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही हैं। नीति इस विचार में दृढ़ता से विश्वास करती है कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नैतिक विचारों और मूल्यों के साथ तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम, करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक कल्पना के साथ अच्छे इंसानों का विकास करना है। इस प्रकार, इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए लगे हुए, उत्पादक और योगदान करने वाले नागरिकों का निर्माण करना है। यह नीति जिन सिद्धांतों पर आधारित हैं, वे हैं:

- लचीलापन: शिक्षार्थियों के लिए अपने विषयों और कार्यक्रमों को चुनने के लिए, और इस तरह अपनी प्रतिभा के हितों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुनना।
- कठिन अलगाव नहीं: ज्ञान की अखंडता और एकता सुनिश्चित करने और सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच और साइलो के बीच हानिकारक पदानुक्रम को खत्म करने के लिए कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक आदि के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं है।
- बहु-विषयक: एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
- वैचारिक समझ पर जोर: केवल परीक्षा के लिए रटकर सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच पर, नैतिकता के साथ-साथ मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। जैसे-सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय और जीवन कौशल जैसे-सहयोग, टीम वर्क, संचार और लचीलापन।
- सीखने के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन: आज की कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है।
- विविधता के लिए सम्मान और स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान: विविधता के लिए सम्मान और सभी पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है।
- कुल समानता और समावेश: कुल समानता और समावेश सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में कामयाब हो सकें।
- संसाधन क्षमता: संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ हिस्सेदारी और गुणवत्ता पर कोई समझौता किए बिना संसाधन दक्षता पर बल दिया गया है।
- शिक्षक और संकाय, सीखने की प्रक्रिया के आत्मा के रूप में: सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में शिक्षक और संकाय होने के नाते, उनकी कठोर भर्ती और तैयारी, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- साधारण लेकिन कड़ी निगरानी और नियामक प्रणाली: स्वायत्तता, सुशासन और अधिकारिता के माध्यम से नवाचार और रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक हल्की लेकिन सख्त निगरानी और नियामक प्रणाली है।
- उत्कृष्ट अनुसंधान: उत्कृष्ट शिक्षा और सतत विकास के लिए एक शर्त के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान को रखा गया है।

- सतत् नीति-निर्माण: शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा जमीनी हकीकतों के नियमित मूल्यांकन के आधार पर सतत नीति -निर्माण की व्यवस्था की गई है।
- भारत और इसकी समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं में एक जड़ता और गौरव, और इसकी दूरदर्शी आकांक्षाओं को एक सटीक तरीके से शामिल किया जाना है, और सभी शिक्षा के लिए एक लंगर और प्रेरणा का स्रोत है।
- शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है: शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है न कि व्यावसायिक गतिविधि या लाभ का स्रोत, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।
- एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ सच्ची परोपकारी निजी भागीदारी: अंत में, एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ सच्ची परोपकारी निजी भागीदारी के प्रोत्साहन और सुविधा में पर्याप्त निवेश करता है।

हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। वे निश्चित रूप से इसके सुचारू कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करने और चुनौतियों को दूर करने में मदद करेंगे।

iv. NEP, 2020 और उच्च शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य शिक्षार्थी को केंद्र में रखते हुए शिक्षा को बदलना है। यह शिक्षा आयोग (1964-66) और न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा आयोग (2012) की सिफारिशों के साथ-साथ नीति के पिछले संस्करणों यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, 1992 में संशोधित, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 और विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 पर आधारित है। वास्तव में, यह वास्तविक शिक्षा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह मुख्य रूप से पहुंच, प्रासंगिकता, इक्विटी, गुणवत्ता और मजबूत आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित करके छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। नीति शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों के लिए कई लाभ प्रदान करती है। यह बचपन की देखभाल और शिक्षा से लेकर स्कूल और उच्च शिक्षा क्षेत्रों तक के पाठ्यक्रम में तालमेल बनाने की परिकल्पना करता है। नीति का प्रमुख फोकस क्षेत्र सीखने के परिणामों में गुणवत्ता सुधार है। एक अन्य फोकस क्षेत्र मूल्यांकन सुधार ला रहा है, जो बहुप्रतीक्षित परिवर्तन रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि NEP,2020 से आने वाले दशक में सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देकर सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को ट्रैक पर लाने की उम्मीद है।

यह ठीक ही कहा गया है कि, "उच्च शिक्षा हर देश में अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, प्रौद्योगिकी अपनाने और स्वस्थ मानव व्यवहार को तय करने में शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है।" नीति का उद्देश्य अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। एक अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से लचीला पाठ्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले चार साल के स्नातक कार्यक्रम में कई निकास बिंदु बनाना, संकाय समर्थन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीयकरण बढ़ाना है। निम्नवत विशेष रूप से उच्च शिक्षा के प्रति नीति की चिंता दर्शाती है:

1 : विशेषताएं, प्रभाव क्षेत्र और हितधारकों के लिए अवसर

विशेषताएं	प्रभाव क्षेत्र	हितधारकों के लिए अवसर
• उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। • बढ़ी हुई इक्विटी और समावेश। • बहु-विषयक और एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की ओर	• गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के माध्यम से बड़े पैमाने पर समेकन संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। बहु-विषयक शिक्षा पर ध्यान दें।	• राज्य सरकार : बेहतर परिणामों की निगरानी और संसाधनों की साझेदारी। शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने वाली बजटीय दक्षता में सुधार। • **HEIs:** भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के स्पष्ट सीमांकन के माध्यम से

3112*_। बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों(HEIs)के मौजूदा स्टैंडअलोन संस्थानों का रूपांतरण। तीन तरफा संस्थागत संरचना यथा-अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और स्वायत्त कॉलेज। HEIs के बढ़ते पैमाने और बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना। • प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को qkıtâl संकाय के लिए कैरियर की प्रगति के रास्ते। कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ लचीली पाठ्यक्रम संरचना। ऑनलाइन लर्निंग और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL)qxa-mğl नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)की स्थापना। सभी उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक। जनता के लिए सूचना का प्रकटीकरण	• सुलभ और समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली। बढ़ी हुई इक्विटी और समावेश। इक्विटी और समावेश में सुधार। ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से इक्विटी और पहुंच में सुधार। • गुणवत्ता और अच्छी तरह से प्रोत्साहित संकाय। संकाय की कमी और गुणवत्ता को संबोधित करना। NRF के माध्यम से अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। • अंतर्राष्ट्रीयकरण सुधारों के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। • शासन के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता। शासन, दक्षता और जवाबदेही में सुधार।	HEI को शुरू करने और संचालित करने में आसानी। शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता में वृद्धि। ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों के संदर्भ में विस्तार और नामांकन बढ़ाने के अवसर। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वयं के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास। निजी HEI के लिए बढ़े अवसर। • संकाय: फैकल्टी के लिए बेहतर सेवा वातावरण। संकाय के लिए कैरियर में उन्नति। प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से प्रशिक्षकों के लिए न्यूनतम करियर गैप और निरंतर शिक्षा। पाठ्यचर्या और शैक्षणिक दृष्टिकोण को डिजाइन करने के लिए संकाय को युक्तिकरण शिक्षण कर्तव्यों और अधिक अवसर। • छात्र: उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रवेश के अधिक अवसर पाठ्यक्रम विकल्पों के लिए अधिक लचीलापन भविष्य के संदर्भ के लिए डिजिटल रूप से संग्रहीत क्रेडिट व्यावहारिक सीखने और व्यावहारिक प्रदर्शन HEI द्वारा बेहतर पारदर्शिता सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से छात्रों पर कम हुआ दबाव विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय छात्रों के लिए अधिक से अधिक एक्सपोजर • उद्योग और अन्य सेवा प्रदाता: ब्लॉक चेन, एआई और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में औद्योगिक खिलाड़ियों के लिए सहयोग का अवसर सिस्टम-व्यापी ICT परिवर्तन से निजी भागीदारी की संभावना होती है वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी खिलाड़ियों के लिए अवसर उद्योग के लिए अवसर। dyı-qı#r 3-wfizı-îr

		निजी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (NETF) के संचालन में विशेषज्ञ के रूप में आगे आने का अवसर

स्रोत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एमएचआरडी)

इस प्रकार, ऊपर वर्णित हितधारकों के लिए सुविधाओं, प्रभाव क्षेत्रों और अवसरों के आलोक में, उच्च शिक्षा के संबंध में NEP, 2020 के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नानुसार प्राप्त किए जा सकते हैं।

- नीति में उच्च शिक्षा के लिए एक नई दृष्टि और वास्तुकला की परिकल्पना की गई है, जिसमें बड़े, अच्छी तरह से संसाधन, जीवंत बहु-विषयक संस्थान उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हैं।
- नीति व्यापक लेकिन लचीली पाठ्यचर्या संरचनाओं, अध्ययन के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और बहु-प्रवेश के साथ-साथ निकास बिंदुओं के माध्यम से व्यापक-आधारित उदार शिक्षा प्रदान करती है।
- नीति स्वैच्छिक और स्व-निर्देशित शासन के लिए सुविधा प्रदान करती है क्योंकि संस्थागत शासन शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय के मामले में स्वायत्तता पर आधारित होगा।
- नीति अच्छे विनियमन को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, क्योंकि विनियमन हल्का लेकिन सख्त होगा, क्योंकि हितों के टकराव को खत्म करने के लिए विनियमन स्वतंत्र निकायों के हाथों में होगा।

हालाँकि, नीति दस्तावेज़ में इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं और इसमें कुछ बाधाएँ हैं जैसे उच्च शिक्षा के लचीले मॉडल को स्वीकार करना, बहु-अनुशासनात्मक संस्थानों की अवधारणा को स्वीकार करना, अधिक से अधिक सार्वजनिक धन की आवश्यकता। समृद्ध डिजिटल बुनियादी ढांचा और इसी तरह, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नीति के सफल निष्पादन के लिए नीति दस्तावेज़ में दिए गए सिद्धांत दिशानिर्देशों को अपनाने, निर्णय लेने की संरचनाओं का नाटकीय सरलीकरण, बजटीय संसाधनों की पुन: प्राथमिकता, प्रणाली में स्वचालन और मशीनीकरण, दृष्टिकोण में परिवर्तन, और योजनाबद्ध और साथ ही साथ आने वाले महीनों और वर्षों में नई नीति का व्यवस्थित कार्यान्वयन।

निष्कर्ष :

हम जानते हैं कि एक देश के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर एक अच्छी तरह से परिभाषित, अच्छी तरह से डिजाइन और व्यापक शिक्षा नीति आवश्यक है क्योंकि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर ले जाती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आज भी उपयुक्त शिक्षा प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। इस प्रकार, सटीक होने के लिए, यह अच्छी तरह से स्वीकार किया गया तथ्य है कि एक अच्छी शिक्षा नीति हमेशा देश में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ले जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायसंगत बनाने की एक स्वागत योग्य और महत्वाकांक्षी पुन: कल्पना है। पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर निर्मित, एनईपी 2020 सतत विकास (एसडी) के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों को अधिक समग्र, लचीला, बहु-विषयक बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। यह नीति बड़े पैमाने पर ऐसे परिमाण के कार्यान्वयन की मांग करती है जो दुनिया में कहीं भी पहले कभी नहीं किया गया था। वास्तविक परिवर्तन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से शुरू होगा और वर्ष 2030 तक जारी रहेगा, जहां परिवर्तन का पहला स्तर दिखाई देने की उम्मीद है। मिशन महत्वाकांक्षी है लेकिन सफल कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यान्वयनकर्ता चुनौतियों को कैसे समझते हैं और इसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए बहुत अधिक स्वीकृति, प्रतिबद्धता, आशावाद, दृष्टिकोण में परिवर्तन और मानसिकता की आवश्यकता होती है। निःसंदेह, भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा करके एक बड़ी छलांग लगाई है, जो 1986 में नीति में अंतिम बड़े संशोधन के लगभग तीन दशक बाद हुई थी। यहां तक कि, मसौदा समिति एनईपी 2020 ने नीति को डिजाइन करने का एक बड़ा प्रयास किया है जो विविध दृष्टिकोणों, शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, क्षेत्र के अनुभवों और हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करता है। मिशन महत्वाकांक्षी है लेकिन कार्यान्वयन रोडमैप यह तय

करेगा कि क्या यह वास्तव में एक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगा जो कृतत1•ह्न को उद्योग और भविष्य के लिए तैयार करता है।

सन्दर्भ:

1. ब्रिटिश काउंसिल, यू.के.; भारत की नई शिक्षा नीति 2020: https://education-services.britishcouncil.org/insights-blog/india%E2%80%99s-new-ed ucation-policy-2020-highlights-and-opportunities 2. 2020: कार्यान्वयन चुनौतियां। https://www.educationworld.in/nep-2020-implementation-challenges/
3. àÂr.Œ.âr. इंटरनेशनल लिमिटेड; राष्ट्रीय ÑÏRT 2020का प्रभाव और हितधारकों के लिए https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2020/08/impact-of-national-education-policy-2020-and-opportunities-for-stakeholders.pdf
4. (VRQzr3TR?r) ÑÏRT * ,2019https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/English1.pdf
5. (एमएचआरडी); *rÈ, 2020 https://www.education.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/NEP Final English O.pdf
6. https://www.education.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/NEP_2020.pdf 7.

बी एल गुप्ता और ए के चौबे (2021); उच्च शिक्षा संस्थान - एनईपी *2020* के संदर्भ में स्वायत्तता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कुछ दिशानिर्देश; IJARESM, Vol. 9, अंक 1, 72-84 ऑनलाइन उपलब्ध: www.ijaresm.com 8.

के. विश्वनाथन.(2020); एरियलिटी चेक ऑन एनईपी *2020:* कार्यान्वयन में *6* प्रमुख चुनौतियाँ। इंडिया टुडे, 14 अगस्त, 2020, https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/a-reality-check-on-nepa 020-major-challenges-in-implementation-1711197 -2020-08-14